आपकी खबरों का संसार...
RNI No.-RJHIN/2015/63826

अतुल्य संसार

संस्करणः जयपुर
हिन्दी समाचार पत्र...
web: www.atulyasansar.com
Digital Edition
www.liveworldnews.in
वर्षः 11 | अंकः 29 | जयपुर, बुधवार 12 अगस्त, 2026 | मूल्यः 2 रुपए | पृष्ठः 4

जलभराव की समस्या... पेज 2

सोनिया बोली मनमोहन... पेज 3

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी-खींचतान

प्रदेश अध्यक्ष से मिले बाड़मेर और अजमेर के नेता; डोटासरा बोले- छोटा-मोटा मनमुटाव, ठीक कर देंगे

जयपुर। प्रदेश में शहरी निकायों और पंचायतीराज चुनावों से पहले जिलों में कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी मतभेद और खींचतान खुलकर सामने आ गई है। बाड़मेर और अजमेर में गुटबाजी को लेकर विरोधी गुट के नेताओं ने जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। बाडमेर से आए पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी के खिलाफ प्रदेशाध्यक्ष से शिकायत की। उन्होंने हरीश चौधरी पर मनमानी करने और गुटबाजी करने के आरोप लगाते हुए शिकायत की। हरीश चौधरी और मेवाराम जैन के खेमों के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। उधर, अजमेर से पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन और उनके समर्थकों ने डोटासरा से मिलकर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ पर गुटबाजी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। हालांकि मीडिया के सामने खुलकर नाम नहीं बताया, लेकिन अंदर खुलकर शिकायतें कीं। डोटासरा ने भी गुटबाजी और आपसी झगड़ों की बात मानी है। उन्होंने कहा- छोटी-मोटी बात संगठन और उनके बीच में है, जिसे हम सब बैठकर बातचीत से ठीक कर देंगे। पूरे राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है।

मेवाराम जैन बोले- बाड़मेर कांग्रेस में गुटबाजी, प्रदेशाध्यक्ष को नाम बताया

पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा- हम कैसे वापस कांग्रेस को मजबूत करें, आपस में गुटबाजी को कैसे खत्म करें, इस मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। बाड़मेर में गुटबाजी बहुत है, उसको खत्म करें और कांग्रेस को एकजुट करें। हमने गुटबाजी करने वाले व्यक्ति का नाम अध्यक्ष को बता दिया है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो और गुटबाजी न हो। पिछले समय में जो कुछ हुआ, उसे भूल जाना चाहिए। जितनी भी गुटबाजी है वो सब खत्म होनी चाहिए।

अजमेर में बाहरी नेता ने बिगाड़ा पूरा सिस्टम

अजमेर के कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा से मिलकर शिकायत की। अजमेर के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा- जिन लोगों को अजमेर में उपेक्षित किया गया, उन लोगों ने आज अपनी बात प्रदेशाध्यक्ष के सामने रखी है। अजमेर में पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। वहां पर एक व्यक्ति की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। हमने उस व्यक्ति का नाम प्रदेशाध्यक्ष को बता दिया है। हमारे यहां बाहर का एक व्यक्ति आकर अजमेर की राजनीति में दखलअंदाजी कर रहा है। बहुत खराबी पैदा कर रहा है। जो छोटे नेता हैं, वह यहां पर जाकर किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की शिकायत लेकर हम प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं।

डोटासरा बोले- छोटे-मोटे मनमुटाव, साथ बैठाकर ठीक कर देंगे

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बाड़मेर और अजमेर में गुटबाजी की बात को माना है। डोटासरा ने कहा- बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के समय किसी कारण से मेवाराम जैन कांग्रेस में नहीं थे। बाद में हाईकमान ने फैसला किया और मेवाराम जैन कांग्रेस में वापस आ गए। अजमेर शहर कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। वहां भी हम लोगों को बैठाकर बात करेंगे।

घूसकांड से चर्चा में आई पिंकी मीणा का फिर ट्रांसफर

सीएम के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव का तबादला; निकाय चुनावों से पहले 183 आरएएस बदले

जयपुर। राज्य सरकार ने निकाय चुनावों से पहले बडा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव, आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी और सवा महीने पहले बहाल हुई चर्चित ॠ पिंकी मीणा का भी ट्रांसफर किया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के एसए समेत तीन अफसरों को एपीओ कर दिया। तबादलों में तीन साल से एक ही जगह पर लगे और गृह जिले में लगे अफसरों के भी बदला गया है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक ही जगह पर लगे और गृह जिलों में लगे अफसरों के तबादले करने के आदेश दिए थे।

सीएम के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव का तबादला

आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी का तबादला टोंक एपीआरटीएस के प्रिंसिपल से अतिरिक्त आयुक्त टीएडी उदयपुर किया गया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव का तबादला किया गया है। श्रीवास्तव को गंगानगर शुगर मिल्स के जीएम के पद पर लगाया है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के एसए कालूराम का तबादला कर दिया है, कालूराम की जगह त्रिलोकचंद मीणा को नागर का एसए लगाया है। मीणा का पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और उपसचिव के पद से एसए के पद पर तबादला किया है।

पिंकी मीणा का सवा महीने बाद फिर तबादला

चर्चित आरएएस पिंकी मीणा का सवा महीने बाद दूसरी बार तबादला कर दिया गया है। पिंकी मीणा को प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग में सहायक निदेशक सवाई माधोपुर से दौसा में सहायक कलेक्टर मुख्यालय के पद पर नई पोस्टिंग दी गई है। पिंकी मीणा को जून में बहाली के बाद पोस्टिंग दी गई थी। 1 जुलाई को उन्होंने सवाईमाधोपुर जॉइन किया था। वे हाईवे घूसकांड मामले में 2021 में सस्पेंड हुई थी, कोर्ट के आदेशों के बाद बहाल किया था।

सीएम भजनलाल शर्मा जेन जी से बात करेंगे

बच्चे मुख्यमंत्री से सवाल भी कर पाएंगे, सोच और उम्मीदों को लेकर होगी चर्चा

बीकानेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में त्वद्गठ्ठ-ं से सीधे संवाद करेंगे। 15 अगस्त को डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के ठीक बाद रविंद्र रंगमंच पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। करीब 15 से 20 साल की उम्र के युवाओं के साथ साल 2047 के भारत को लेकर उनके सपनों, सोच और उम्मीदों पर चर्चा की जाएगी। अभी ये तय नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें सीधा हिस्सा ले सकता है या फिर आमंत्रित युवाओं को भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।

स्टूडेंट्स को अपने विचार मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर मिलेगा। वे यह भी बता सकेंगे कि वे 2047 में भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। युवाओं को मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का अवसर भी दिया जाएगा। यानी कार्यक्रम एकतरफा भाषण के बजाय सवाल-जवाब और संवाद पर केंद्रित रहेगा।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रेट में सदस्यों की नियुक्तिः सरकार ने कोर्ट में नियुक्ति का आदेश पेश किया

कहा-जल्द चेयरमैन की नियुक्ति भी करेंगे

जयपुर। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) में दो सदस्यों की नियुक्ति कर दी हैं। इसकी जानकारी आज सरकार की ओर से कोर्ट में दी गई। उन्होंने कहा कि हमने सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी अतर सिंह नेहरा और सेवानिवृत्त वीरेंद्र सिंह बांकावत को रेट जयपुर पीठ में सदस्य नियुक्त कर दिया है। वहीं रेट चैयरमेन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जो जल्द कर दी जाएगी। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की

खंडपीठ ने सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी। बता दें कि पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि वह 7 दिन में रेट के खाली पदों पर नियुक्तियां कर दे अन्यथा डीओपी सचिव पेश हो जाए।

अगर ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते हो तो इसको बंद कर दो

दरअसल, वकील दिलीप सिंह कुरका, वकील संदीप कलवानिया सहित अन्य वकीलों की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके रेट में अध्यक्ष और सदस्यों के नहीं होने पर सुनवाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था। इस सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते हो तो इसको बंद कर दो। आपने इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर कर दिए, कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे।

पिछले 4 महीने से चेयरमैन का पद खाली

रेट चेयरमैन के रूप में विकास सीताराम भले का 19 मार्च 2026 को तबादला होने के बाद से यह पद खाली चल रहा है। इसके अलावा रेट में चार सदस्यों के पद भी हैं। इसमें से दो पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। एक सदस्य के पद पर पूर्व आईएएस अधिकारी प्रकाश शर्मा को अध्यक्ष का कार्यभार दे रखा हैं। वहीं न्यायिक सदस्य पूनम दरगन बीमारी के रेगुलर नहीं हैं।

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले जयपुर में बड़ा फेरबदल

जयपुर से 16 फील्ड ऑफिसर बदले, जिनका चुनाव में रहता है अहम रोल

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। आज(मंगलवार) कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करके 180 से ज्यादा राजस्थान प्रशासनिक सेवा ऑफिसर के तबादल किए हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां 16 ऐसे फील्ड ऑफिसर (उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर) बदले हैं, जिनका चुनाव में अहम काम रहता है। कार्मिक विभाग से जारी सूची में चौमूं, जोबनेर, दूदू, जयपुर शहर (साउथ), फागी, चाकसू, जमवारामगढ़,

माधोराजपुरा, शाहपुरा, मौजमाबाद, रामपुरा डाबरी उपखंडों के उपखंड अधिकारी के तबादले किए है। जबकि चौमूं, जमवारामगढ़, शाहपुरा, आमेर, सांभर के सहायक कलेक्टर को भी बदला गया है। इन सभी अधिकारियों का काम आगामी चुनावों की प्रक्रिया को करवाना है। पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति चुनावों में अहम रोल रहता है। नामांकन भरने, वार्डों की आरक्षण लॉटरी करने, चुनाव करवाने और रिजल्ट जारी करने से जुड़े तमाम काम एसडीओ और सहायक कलेक्टर ही करवाते हैं।

वन विभाग में 69 आईएफएस अफसरों के ट्रांसफर

आरएफएस से आईएफएस बने 22 अफसरों को पोस्टिंग, 14 अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज, शैलजा देवल पर्यावरण सचिव बनीं

जयपुर। राज्य सरकार ने देर रात वन विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 69 आईएफएस अफसरों के तबादले-पोस्टिंग की है। आरएफएस से आईएफएस बने 22 अफसरों को उनके प्रमोशन के सात महीने बाद पोस्टिंग दी गई है। 14 आईएफएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वन विभाग के हेड अरिजीत बनर्जी का पदनाम बदलकर अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स कर दिया है। वन विभाग के मुखिया का पदनाम देश के कई राज्यों में बदला गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव विजय एन का तबादला मुख्य वन संरक्षक स्थापन जयपुर के पद पर किया है।

पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल को हाईकोर्ट से राहत

आपराधिक कार्रवाई रद्द, कहा- सिविल, राजस्व मामलों को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुजरात की पूर्व राज्यपाल दिवंगत कमला बेनीवाल के खिलाफ करोडों रुपयों की सरकारी जमीन हड़पने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्ध कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की बेंच ने यह आदेश कमला बेनीवाल सहित 17 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा-जब मामला सिविल और राजस्व अदालतों में लंबित हो तो उसे आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता है। यह पूरा विवाद कृषि भूमि के पट्टे, स्वामित्व और खातेदारी अधिकारों से संबंधित है। जो मूल रूप से सिविल और राजस्व प्रकृति का है। ऐसे में सिविल विवाद को आपराधिक रूप देना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश और एडीजे कोर्ट के रिवीजन आदेश को रद्द कर दिया।

अलग-अलग कानूनी फोरम पर मामले लंबित

अदालत ने कहा- इस मामले से संबंधित केस अलग-अलग कानूनी फोरम में लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं को

साल 1958 में दिए गए खातेदारी अधिकार, जयपुर विकास प्राधिकरण का जमीन अवाप्ति करना, भू-राजस्व अधिनियम के तहत रेफरेंस और मुआवजे का वितरण जैसे मुद्दे अभी भी हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन हैं। जब तक सक्षम सिविल और राजस्व अदालतें इन अधिकारों को रद्द नहीं कर देतीं, तब तक धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप नहीं बनता है।

करीब 14 साल पहले हुई थी शिकायत

इस मामले में करीब 14 साल पहले संजय किशोर अग्रवाल ने 16 अगस्त 2012 को कोर्ट में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि साल 1951 में सरकार ने अनुपयोगी कृषि भूमि को 20 साल के लिए खेती पर देने की योजना बनाई थी। बाद में संशोधन से 20 साल की अवधि को बढ़ाकर 25 साल कर दिया। कहा गया कि 25 साल बाद जमीन पुन राज्य सरकार की हो जाएगी।

सरकार ने 5 जनवरी 1953 को राजेंद्र सिंह और अन्य की किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति झोटवाड़ा को भूमि आवंटित की। जबकि यह समिति 13 फरवरी 1953 को रजिस्टर्ड हुई थी। समिति के सदस्य खेती की जगह अन्य कार्य करने लग गए, लेकिन उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। 25 साल पूरे होने के बाद सरकार ने जमीन वापस नहीं ली। इसके कुछ साल बाद जेडीए ने पृथ्वीराज नगर योजना के लिए जमीन अवाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी। समिति सदस्यों को अवाप्ति के बदले मुआवजे के रुप में 15 फीसदी विकसित जमीन देने का ऑफर दिया गया।

कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया

इस बीच अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता ने अपनी रिपोर्ट में माना कि समिति सदस्य गलत और झूठे तथ्यों के आधार पर मुआवजे में जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के वर्तमान सदस्यों में से एक भी सदस्य समिति का ऑरिजनल सदस्य नहीं हैं। इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके करीब 400 करोड़ रुपए की 1516 वर्गमीटर जमीन मुआवजे में ले ली है, लेकिन करधनी थाने ने मामले में एफआर लगा दी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एफआर का विरोध करते हुए कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 मई 2014 को कमला बेनीवाल सहित अन्य के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर एडीजे कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया था। इन दोनों आदेश को रद्द करने के लिए आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई थी।

एडवोकेट लक्ष्मण राम सैनी को उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति का बनाया सदस्य

एडवोकेट सैनी ने पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी का किया आभार व्यक्त

सुमेर सिंह राव/उदयपुरवाटी। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट लक्ष्मण राम सैनी को उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति का सदस्य बनाए जाने पर एडवोकेट सैनी ने भाजपा के कद्दावर नेता एवं उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी का तहेदिल से आभार व्यक्त किया है द्य एडवोकेट लक्ष्मण राम सैनी को सतर्कता समिति का सदस्य बनाए जाने पर उदयपुरवाटी के कई गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोगों एवं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियो ने उन्हें बधाई दी है द्य सतर्कता समिति का सदस्य बनाए जाने पर एडवोकेट सैनी ने कहा कि वह हमेशा भाजपा के मार्गदर्शन और स्नेह के लिए सदैव आभारी रहेंगे जनहित में पूरी निष्ठा ईमानदारी एवं समर्पण के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे।

रामपुरा निवासी बाबूलाल ताखर बने जयपुर ग्रामीण पूर्व के कांग्रेस जिलाध्यक्ष

विजयपाल सैनी शाहपुरा। शाहपुरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ में संगठनात्मक विस्तार के तहत शाहपुरा क्षेत्र को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अनुमति से प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम स्वामी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रामपुरा निवासी बाबूलाल ताखर को जयपुर ग्रामीण पूर्व का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। ताखर की नियुक्ति के बाद शाहपुरा पहुंचने पर मुख्य बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गोपाल लाल मीणा, ग्यारसी लाल टोकस, सीताराम, बंशीधर यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

श्री मनोकामेश्वर शिव मंदिर सहस्त्रगढ़ सम्मान समारोहः भगवान भोलेनाथ की सजी आकर्षक फुल बंगला झांकी

जयपुर। श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री गणेश मित्र मंडल संस्था के द्वारा घाटगेट स्थित श्री मनोकामेश्वर शिव मंदिर के जीणोद्धार सावन मास के शुभ अवसर पर सहस्त्रगढ़ और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन मे निर्तमान महापौर कुसुम यादव ने मुख्य अतिथि शिरकत की। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का पांच विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात भगवान को नवीन पोशाक धारण कराकर फूल बंगला झांकी सजाई। भक्तों के द्वारा भोलेनाथ की महाआरती बैंड वादन के साथ की गई। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन गायको ने भगवान भोलेनाथ की एक से बढ़कर एक भजन सुना कर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। आयोजन में भामाशाहों का माला दुपट्टा और भगवान भोलेनाथ की छवि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंडल परिवार के कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार लोधीका, सचिव कैलाश शेरगड़िया, स्वागत मंत्री मनीष अग्रवाल, अध्यक्ष राजकुमार पलडिया, हरशिव मीणा, शंकर लाल यादव, संरक्षक आशुतोष गोयल, बाबूलाल जांगिड, कन्हैयालाल साहू, मुन्नालाल सोनगरा, यशपाल सिंह, केहर सिंह, मंडल परिवार के संयोजक अतुल गोयल,रवि नयर विधायक प्रत्याशी आदर्श नगर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया । मंडल परिवार के सदस्य श्रद्धालु पदाधिकारी मौजूद रहे ।

बच्चों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई

जयपुर। एकता नगर धवास हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड स्थित D.N.पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान एवं मिशन स्पंदन के अंतर्गत विकसित भारत की ओर एक सशक्त कदम दादी प्रकाशमणि जी की पावन स्मृति में कक्षा नवी से 12वीं कक्षा तक के 400 बच्चों को नशा न करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई जिसमें जगदंबा नगर केंद्र की बी.के. शशि तथा बी.के. मंजू एवं विद्यालय निदेशक बी.पी. गुर्जर तथा संतोष देवी गुर्जर उपस्थित रहे।

जैन धर्म व भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए दल विदेश यात्रा करते हुए ओरलैंडो पहुँचे

जयपुर। जैन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए जय जिनेंद्र ग्रुप महावीर नगर का 10 सदस्यीय दल आज 4 सप्ताह के लिए जयपुर से विदेश यात्रा करते हुए ओरलैंडो पहुंचे इस यात्रा के दौरान यह दल जैन धर्म व भारतीय संस्कृति का प्रचार- प्रसार करेगा। इस बारे में श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय महामंत्री व ग्रुप के सुरेंद्र जैन पांड्या ने बताया कि यात्रा करते हुए ओरलैंडो पहुंचे वहाँ पर पदमपुरा के एतेहासिक पंच कलायन में आचार्य वर्धमान सागर जी द्वारा प्रीतिष्ठ महावीर भगवान और पारसनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन हुए यह दल यूएसए में चार सप्ताह के दौरान विभिन्न स्टेट की यात्रा करते हुए सभी जैन मंदिर के दर्शन करेंगे और जैन समाज के लोगों से मिलकर वहां मिलकर धर्म चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा की शुरुआत संस्फ्रांस्को से की एयरपोर्ट से आते हुए सबसे पहले जैन मंदिर के दर्शन से हुई वहां पर दोनों धर्मों का एक ही मंदिर है, जहां पर दोनों धर्मावलंबी मिलकर पूजा कर रहे हैं। इस दल में रिटायर्ड न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जैन ,सुरेश काला, कैलाश जैन व सुरेश सोगानी सहित अंध लोग शामिल है।

रक्तदान शिविर मेंदिखा उत्साह, 273 यूनिट रक्त एकत्रित

जयपुर। निश्चय संस्थान की ओर से आज 6 वें रक्तदान शिविर का आयोजन श्याम नगर स्थित ग्रास फील्ड क्लब में किया गया। इस मौके पर शिविर में करीब 273 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष अमन अग्रवाल ने बताया कि मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉ .अंकित माथुर, रोटरी के चार्टर प्रेसिडेंट सुधीर जैन गोधा, राजेंद्र गुप्ता व गोविन्द जाखोटिया मौजूद रहे। इस दौरान शिविर में 273 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि सभी रक्तदाताओं को एक पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत पोधों का वितरण किया गया। अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि शिविर में अपोलो क्लिनिक की और से एक नि:शुल्क जांच शिविर भी लगाया गया।शिविर में नितिन ,विवेक ,मोहक अविनाश ऋषि सिंह, राकेश, कृष्ण और पूरी निश्चय की टीम ने सभी रक्तदाताओं और अतिथियों का आभार जताया।

जलभराव की समस्या को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने सौंपा ज्ञापन

विजयपाल सैनी शाहपुरा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अंतर्गत शहर में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने परियोजना के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि शहर के कई रास्तों एवं सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कें जलमग्न हो जाती है तथा स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश खुडानिया ने नगर कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर जल भरा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर परियोजना के अधिकारियों से मांग की। जलभराव

वाले रास्तों एवं सड़कों पर पानी की निकासी के लिए स्थायी एवं प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि बारिश के दौरान लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। रैंप प्राइस स्थित भोम दास जोहड़ मैं पानी की सफाई करवा कर जोहड़ में फल फूल रही मछलियों की सुरक्षा हेतु कार्य किया जाए क्योंकि जन आस्था से जुडा होने के कारण उसके चारों ओर बाउंड्री वाल करके इसे सुरक्षित किया जाए शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्थित तीन गेट दिल्ली दरवाजा अमृतसर दरवाजा मनोहरपुर दरवाजा के रंग रोगन करवरकर सुंदर कलाकृतियों से सजाया जाए गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित पुरानी बावड़ी का पुनः जीर्णोद्धार करवाकर रंग रोगन करवाया जाए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी, जिलाध्यक्ष निहाल पलसानिया, न्यू वर्तमान उपसभापति राजेंद्र सारण, नगर कांग्रेस कमेटी संगठन महासचिव बनवारी लाल तिवारी, महासचिव वकील खान, पूर्व चेयरमैन प्रेम देवी जाट, प्रहलाद पलसानिया, पूर्व पार्षद हनुमान सहाय सैनी, रामेश्वर गोरेठा, जितेंद्र शर्मा, विशाल पलसानिया, राजेंद्र शर्मा, आलोक खंडेलवाल, असलम कुरैशी, रामावतार गुर्जर नेता प्रतिपक्ष, गिरधारी लाल जाट, अमरचंद यादव, धर्मपाल यादव, हंसराज देवन्दा, रामावतार यादव सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद थे।

राजस्थान महिला कांवड़ संघ की ओर से महिला सशक्तिकरण और एकता का संदेश देती कांवड़ यात्रा

दीपचंद शर्मा सीकर। राजस्थान महिला कांवड़ संघ, सीकर की इस भक्तिमय कांवड़ यात्रा ने भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और भक्ति के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति और महिला एकता का भी सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश दिया। इस यात्रा में महिलाओं ने पवित्र लोहार्गल कुंड में स्नान करने के बाद पवित्र है । गोमुखी से कांवड़ भर श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मंदिर के मुख्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री अश्विनी दास महाराज द्वारा पूजा अर्चना आरती के बाद महिलाओं ने पवित्र यात्रा शुरू की । यह यात्रा पाँच सालों से की जा रही है। इस यात्रा में महिलाओं ने केवल श्रद्धालु के रूप में भाग नहीं लिया, बल्कि यात्रा की विभिन्न व्यवस्थाओं, सेवा, समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व की जिम्मेदारियाँ भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाई। राजस्थान महिला कांवड़ संघ, सीकर की । इस भक्तिमय एवं सफल कांवड़ यात्रा में सभी बहनों ने उत्साह, श्रद्धा, सेवा और आपसी सहयोग के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीलम मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कांवड़ यात्रा में सीमा पांडे, कमला कृष्णियां, रितु पारीक, किरण तिवाड़ी, सरिता डोकवाल, उषा छींपा, उर्मिला दीक्षित, अनामिका

मिश्रा, अंजू शर्मा, मीनू शेखावत, सुशीला खंडेलवाल, अमृता बागड़िया, भावना अरोड़ा, अंजु इंदौरिया, पिंकी अग्रवाल, सुनीता सैनी, बबीता जलधारी, काजल इंदौरिया, वंदना मिश्रा, मधु मिश्रा, अनिता चिरानिया, भारती पाराशर, ममता गोयल, सरोज अग्रवाल, इन्दु अग्रवाल, संगीता सराफ एवं रवीना शर्मा सहित कई बहनों ने सहभागिता निभाई।

इस पावन यात्रा के दौरान सभी बहनों ने प्राचीन शिव मंदिर में विधि-विधान एवं श्रद्धा के साथ कांवड़ अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और देश की सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना की।

तिरंगे की सुंदर टोपी लगाकर महिलाओं यात्रा की शुरुआत की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगे का संदेश दिया। यह यात्रा इस बात का सुंदर उदाहरण रही कि महिलाएँ जब संगठित होकर किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती हैं, तो वे हर जिम्मेदारी को पूरी क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन और समर्पण के साथ निभा सकती हैं। धार्मिक आस्था के साथ महिलाओं का यह सामूहिक प्रयास समाज में नारी शक्ति, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और परस्पर सहयोग की भावना को मजबूत करता है। नीलम मिश्रा ने कहा कि यह कांवड़ यात्रा केवल भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और आस्था की यात्रा नहीं, बल्कि नारी शक्ति एवं महिला सशक्तिकरण का संदेश देने वाली एक प्रेरणादायक पहल भी है। ऐसी यात्राएँ महिलाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने, नेतृत्व करने, एक-दूसरे का सहयोग करने और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती हैं। राजस्थान महिला कांवड़ संघ, सीकर की इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि भक्ति और नारी शक्ति जब साथ चलती हैं, तो आस्था के साथ समाज में एकता, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। भक्ति के साथ नारी शक्ति का संकल्प, यही इस कांवड़ यात्रा की विशेष पहचान रही।

123 RPS अधिकारियों का ट्रांसफर, जयपुर कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल

48 ट्रेनी आरपीएस को भी पोस्टिंग; DGP ने दिए तुरंत जॉइन करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। मंगलवार देर रात राजस्थान पुलिस सेवा के 123 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के ट्रांसफर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सभी अधिकारियों को तुरंत जॉइन करने के ऑर्डर दिए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 12 अधिकारियों को बदला गया है। ट्रांसफर लिस्ट के साथ 48 ट्रेनी आरपीएस को भी पोस्टिंग दी गई। इससे पहले मंगलवार शाम को राजस्थान सरकार ने 183 RAS अधिकारियों का तबादला किया था। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक ही जगह पर लगे और गृह जिलों में लगे अफसरों के तबादले करने के आदेश दिए थे।

जयपुर कमिश्नरेट में क्या बदला?

नई ट्रांसफर लिस्ट में नरेन्द्र कुमार को एसीपी पुलिस कंट्रोल रूम, हेमराज को एसीपी साइबर क्राइम, जेठू सिंह को एसीपी सोडाला, दिलीप कुमार मीणा को एसीपी शास्त्री नगर लगाया गया है। संग्राम सिंह को एसीपी साइबर क्राइम, जितेन्द्र सिंह को एसीपी आदर्श नगर, कृष्णराज जांगिड़ को एसीपी चौमूं, नरेन्द्र कुमार को एसीपी महिला सेल में भेजा गया है। डॉ. पूनम को एसीपी अशोक नगर, शिवदयाल बलाई को एसीपी मालवीय नगर, दीपक कुमार खंडेलवाल को एसीपी सांगानेर तथा धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को एसीपी बगरू लगाया गया है।

10 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर कैंसिल

लिस्ट में अनिल जसोरिया, अब्दुल रहमान, हजारी लाल खटाना, विजय कुमार आर्य, सुरेंद्र कुमार, मनीष कुमार शर्मा, नरेंद्र कुमार दायमा, सुरेंद्र कुमार, बृजेश कुमार जाटव और रमेश कुमार पारीक का ट्रांसफर कैंसिल किया गया है। इसके अलावा 48 ट्रेनी **RPS** अधिकारियों को विभिन्न जिलों और इकाइयों में पोस्टिंग दी गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बीजू जॉर्ज जोसफ ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। ओमप्रकाश गोदारा को एसीपी कोतवाली लगाया गया है। जबकि नेहा राव को एसीपी ट्रैफिक साउथ (सेकेंड) और कमल कुमार को एसीपी ट्रैफिक नॉर्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर, अरुण कुमार को सीडीईओ बीकानेर लगाया

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ट्रांसफर लिस्ट जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में कई जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं। विभाग की ओर से अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुसूया को चूरू, संगीता मानवी को भरतपुर की जिम्मेदारी

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अनुसूया को संयुक्त निदेशक चूरू के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं संगीता मानवी को संयुक्त निदेशक भरतपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह अरुण कुमार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर के पद पर लगाया गया है। वहीं प्रेमचंद अमेरा को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर के पद पर पदस्थापित किया गया है। जबकि महेंद्र कुमार शर्मा को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में DEO स्तर के कई अधिकारियों के भी पदस्थापन बदले गए हैं। दरअसल, शिक्षा विभाग में JD, DD और DEO स्तर के अधिकारियों की भूमिका स्कूल शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण होती है। जिलों में शिक्षा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन, स्कूलों की मॉनिटरिंग, शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक मामलों और विभागीय व्यवस्थाओं की निगरानी में इन अधिकारियों की अहम जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में अधिकारियों के तबादले के बाद संबंधित जिलों में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुसार कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग में लंबे समय बाद एक साथ कई स्तर के अधिकारियों के तबादले किए जाने से विभागीय कामकाज में भी बदलाव आएगा। अब नए पदस्थापित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा विभाग की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।

राजस्थान में कमर्शियल वाहनों से ऐंठते थे घूस की मोटी रकम, एसीबी के हत्थे चढ़े 'वसूली गैंग' के 2 दलाल...

जयपुर। राजस्थान में ब्यावर के तत्कालीन परिवहन निरीक्षक जल सिंह मीणा से जुड़ा भ्रष्टाचार प्रकरण नेशनल हाईवे पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों से की जाने वाली करोड़ों रुपये की संगठित मासिक अवैध वसूली का गंभीर मामला है। इस पूरे नेक्सस की पोल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी सर्विलांस और खुफिया विंग के जरिए खोली थी।

अब इस केस में ताजा घटनाक्रम के तहत ACB ने इस संगठित वसूली गैंग के दो और मुख्य दलालों- जगजीत सिंह उर्फ जगत बन्ना और ऋषिराज सिंह राठौड़ को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशों पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यावर के मोटर वाहन निरीक्षक जल सिंह मीणा व अन्य के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में गहन अनुसंधान के बाद एसीबी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जगजीत सिंह उर्फ जगत बन्ना और ऋषिराज सिंह राठौड़ (निवासी जिला अजमेर) के रूप में हुई है। एसीबी की टीम ने पुलिस अभिरक्षा में दोनों आरोपियों से उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और केस से जुड़े अन्य तथ्यों के संबंध में गहन पूछताछ की। साक्ष्यों की पुष्टि होने और विधिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज...

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7ए और भारतीय न्याय संहिता (**BNS**-2023) की धारा 61 (2) के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर दोनों आरोपियों को आज 11 अगस्त को एसीबी मामलों की विशेष अदालत, अजमेर में पेश किया गया।

क्या है पूरा मामला...

इस साल जनवरी में, **ACB** की विजिलेंस विंग को खुफिया इनपुट मिले थे कि अजमेर, ब्यावर और केकड़ी जिलों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बड़ा अवैध वसूली रैकेट चलाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए **ACB** ने जनवरी 2026 में परिवहन निरीक्षक जल सिंह मीणा और उनके दलालों के ब्यावर, विजयनगर और अजमेर स्थित कई ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।

होटल बना था वसूली का अड्डा...

जांच में सामने आया कि ब्यावर के एक प्रसिद्ध होटल को इस काली कमाई को इकट्ठा करने और बांटने का मुख्य केंद्र बनाया गया था। दलाल दिनभर हाईवे से अवैध राशि बटोरते थे।

संसद परिसर में एनडीए-कांग्रेस सांसद आमने-सामने आए

बीजेपी सांसद ने पूछा- राहुल झारखंड क्यों नहीं गए, प्रियंका का जवाब- वे छात्रों से मिल चुके

नई दिल्ली। संसद परिसर में NDA और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार को एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। NDA सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने भी आ गए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका मुस्कुराती हुई उनके पास गईं और कहा- राहुल झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही पहले 11 बजे तक स्थगित की गई।

दोपहर 2 बजे सदन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन है। तीन हफ्तों के दौरान संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे के कारण प्रभावित रही है। विपक्ष दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहा है। सरकार ने सोमवार को कहा कि अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि, राहुल ने कहा कि हमें शाह की राय नहीं सुननी बल्कि यह जानना है कि छात्रों पर पुलिस एक्शन का आदेश किसने दिया था।

वंदे मातरम् बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'वंदे मातरम्' बिल को मंजूरी दे दी। अब राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसके अपमान या गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

रिजिजू बोले- केरलम नाम वाले बिल पर वेणुगोपाल नहीं बोल सके, इसका दुख

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि केरलम के पुराने नाम को बरकरार रखने वाला बिल बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, केरलम एक खूबसूरत राज्य है और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सीनियर सांसद हैं। मुझे दुख है कि बिल पास होने के दौरान वे अपनी बात नहीं रख सके।

लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

हंगामे के बीच लोकसभा में दो बिल पास

हंगामे के बीच लोकसभा में दो बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इनमें केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) बिल, 2026 शामिल है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल का नाम बदलने वाला बिल पेश किया। नारेबाजी के बीच इसे बिना बहस के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) बिल, 2026 पेश किया। लगातार हंगामे के बीच यह बिल भी बिना बहस के पारित हो गया। लोकसभा अब तक 11 बिल पारित कर चुकी है। इनमें केवल दो बिलों पर बहस हुई है, जबकि बाकी बिल विपक्ष के विरोध के बीच बिना चर्चा के पारित किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा, राहुल गांधी डरे हुए हैं और यही वजह है कि उन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। जब अमित शाह सदन में बोलने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी को सदन चलने देना चाहिए।

हंगामे के बीच लोकसभा में 2 बिल पास

विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने केरल का नाम केरलम करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़े दो बिल बिना चर्चा के पास कर दिए। लोकसभा अब तक 11 बिल पास कर चुकी है, जिनमें सिर्फ 2 पर चर्चा हुई है।

सरकार सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर चर्चा के लिए तैयार

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, सरकार गृह मंत्री के बयान और सुरक्षाबलों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं खनिज, खदान और ट्रिब्यूनल से जुड़े तीन बिलों पर चर्चा के लिए 2-3 घंटे का समय तय किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने वंदे मातरम् बिल को दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को 'वंदे मातरम्' बिल को मंजूरी दे दी। यह बिल 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया था। इस बिल के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर कानूनी सुरक्षा मिल गई है। यह कानून 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से रोकने वाले कानून में संशोधन करता है। इसके तहत 'वंदे मातरम' के गायन में जानबूझकर बाधा डालना, किसी सभा को इसे गाने से रोकना या इसका कानून के दायरे में आने वाला अपमान करना अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। दूसरे या बाद के दोषसिद्ध मामलों में कम से कम एक साल की जेल का प्रावधान भी है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- छात्रों के मामले पर झूठ फैला रही है कांग्रेस

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- कांग्रेस छात्रों के हितों को लेकर लगातार झूठ फैला रही है। राहुल के पास तथ्यों की कमी है। विपक्ष के नेता न तो संसद में आना चाहते हैं और न ही सरकार के जवाब सुनना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ झूठ फैलाना और घड़ियाली आंसू बहाना है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सोमवार को लाठीचार्ज के बाद शाम में ही घटना की निंदा की थी। उन्होंने पीएम मोदी की तरह दो हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का इंतजार नहीं किया।

बंगाल एसआईआर- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी

ट्रिब्यूनल के फैसलों में देरी पर कहा- इस रफ्तार से तो अगले इलेक्शन आ जाएंगे

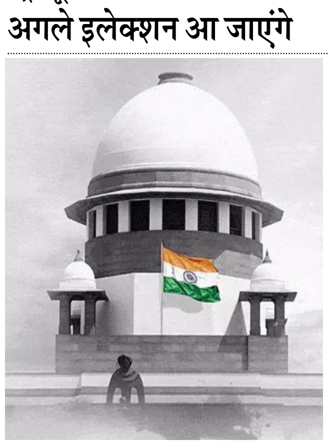

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हटाए गए नामों से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों के फैसलों की डिटेल्स देने को कहा है। ये अपीलीय ट्रिब्यूनल उन लोगों की अर्जियों पर सुनवाई करते हैं, जिनके नाम बंगाल एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की संख्या, काम के घंटे और मामलों के निपटारे की रफ्तार जैसे मुद्दों की जांच करने पर सहमति जताई। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामलों के निपटारे के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकते।

कोर्ट ने पूछा- कितनी अपील आईं, कितनों पर फैसला हुआ

कोर्ट ने **EC** से राज्य में एसआईआर से जुड़े मामलों में कितनी अपीलें दाखिल हुईं, कितनों पर फैसला हुआ और कितने मामले अभी लंबित हैं, इसकी जानकारी मांगी है। इससे यह साफ होगा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ लोगों की ओर से दाखिल अपीलों पर ट्रिब्यूनल ने अब तक कितनी कार्रवाई की है। ट्रिब्यूनल में करीब 34 लाख अपील पेंडिंग हैं। कोर्ट ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। चौधरी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने स्ढ्ढक्रसे जुड़े मामलों का जल्द निपटारा कराने की मांग की थी।

सोनिया बोलीं- मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में एक थे

उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बीजेपी सरकार से अलग, इतिहास उन्हें सम्मान से याद करेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने आर्टिकल में मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना की। सोनिया ने लिखा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा था। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल, लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर सम्मान से याद करेगा। सोनिया ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ लॉबी कैंपेन सुनियोजित और संगठित था। इसमें अफसरशाही से लेकर मीडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी और निश्चित तौर पर आरएसएस और BJP से जुड़े लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि आज यह कैंपेन अपने तय अंत यानी शून्य पर पहुंच गया है और डॉ. सिंह हर मामले में बेदाग साबित हुए हैं।

5 पॉइंट में समझें कोयला ब्लॉक आवंटन मामला

मामला क्या था: 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक का आवंटन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL), नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NLC) और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Hindalco) को किया गया था। आरोप था कि पहले आवंटन की सिफारिश NLC के पक्ष में थी, लेकिन बाद में हिंदाल्को को शामिल कर फैसला बदला गया।

मनमोहन सिंह पर आरोप: उस समय सिंह प्रधानमंत्री के साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे थे। आरोप था कि उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बावजूद मामले को दोबारा खुलने दिया और हिंदाल्को को शामिल करने वाले आवंटन को मंजूरी दी।

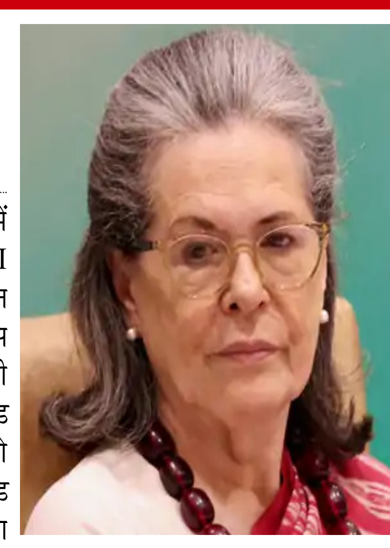

CBI की जांच: CBI ने जांच के बाद 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं बनता। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट खारिज कर दी और 2015 में सिंह समेत अन्य लोगों को समन जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्लिन चिट दी: इस साल 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट का समन वाला आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने और संज्ञान लेने का कोई ठोस कारण नहीं था।

मामला खत्म: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनमोहन सिंह के खिलाफ इस मामले की आपराधिक कार्यवाही खत्म हो गई। उनका 27 दिसंबर 2024 को निधन हो चुका था।

सोनिया बोलीं- 29 जुलाई राजनीतिक इतिहास का अहम दिन

सोनिया गांधी ने कहा कि 29 जुलाई भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। मनमोहन सिंह ईमानदारी और सत्यनिष्ठा वाले इंसान थे। उनके खिलाफ अभियान सुनियोजित और संगठित था। इसमें नौकरशाही, मीडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी के साथ आरएसएस और **BJP** से जुड़े लोग शामिल थे। सोनिया ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक बहस के सबसे दुखद अध्यायों में से एक का अंत करता है। मनमोहन सिंह हर आरोप में पाक-साफ साबित हुए हैं। मोदी सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनी **ED** और **CBI** जैसी एजेंसियों का साफ तौर पर गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा- इन एजेंसियों का मकसद नेताओं पर दबाव बनाना रहा है। नेताओं को या तो दबाव डालकर चुप करा दिया जाता है, या चालाकी से **BJP** में शामिल कर लिया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें मंत्री पद भी दे दिया जाता है।

पन्ना की खदान में मिला 50 लाख का हीरा

बारिश के पानी में चमक रहा था; साझेदार बोले- नीलामी से मिली रकम से शादी करेंगे

पन्ना। पन्ना जिले की एक खदान में 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला है। एक्सपर्ट्स ने इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। हीरे को सरकारी दफ्तर में जमा करा दिया गया है। इसे अगली नीलामी में रखा जाएगा। इससे मिली रकम रॉयल्टी और टैक्स काटने के बाद खदान मालिकों को दी जाएगी। खदान में 7 साझेदार- अखिलेश पाल, संतोष कुशवाहा, शर्मन पाल, अरुण रावत, हेमचंद्र पाल, जमुना पाल और हीरालाल कुशवाहा हैं।

दिल्ली में साइबर ठगी का खुलासा, 9 आरोपी पकड़े: कतर-दुबई तक फैला था नेटवर्क, 16 करोड़ रुपए की धोखाधडी सामने आई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने देशभर में साइबर फ्रॉड से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर निवेश के नाम पर लोगों का ठगने का आरोप है। इन्हें पिछले दिनों केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब से पकड़ा गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इनका नेटवर्क कतर और दुबई से जुडा है। वहां बैठे लोग इनकी मदद करते थे। इनके खिलाफ 34 शिकायतें पुलिस को मिली थीं। इन पर 15.71 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है।

फर्जी ट्रेडिंग मुनाफा दिखाकर निवेश के लिए भरोसा दिलाया

ताजा मामला दिल्ली के पालम कॉलोनी के निवासी की शिकायत के बाद सामने आया। उसने बताया कि उसे निवेश सीखने वाले सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़कर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए मुनाफा दिखाकर निवेश कराया गया। आरोपियों ने खुद को मार्केट एनालिस्ट और निवेश विशेषज्ञ बताया। पीड़ित ने शुरुआत में अलग-अलग बैंक खातों में 4.82 लाख रुपए जमा किए। भरोसा बढ़ाने के लिए उसे थोड़ी रकम निकालने की अनुमति दी गई। इसके बाद आरोपियों ने आईपीओ अलॉटमेंट के नाम पर उससे 7.81 लाख रुपए और जमा करने को कहा। ठगी का शक होने पर पीड़ित ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत की। इसके बाद दक्षिण-पश्चिम जिले के साइबर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

महाराष्ट्र से शुरू हुई जांच दूसरे राज्यों तक पहुंची

महाराष्ट्र से शोएब दिलावर अरेस्ट: जांच टीम ने रकम के लेनदेन और डिजिटल सबूतों की पड़ताल की। इनकी कड़ियां कई राज्यों से जुड़ी मिलीं और जांच पहले महाराष्ट्र पहुंची। इसके बाद शोएब दिलावर सैयद को नंदुरबार से गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल की जांच में आपत्तिजनक चैट और डिजिटल सबूत मिले।

सूरत से चार लोग गिरफ्तार: पुलिस के मुताबिक, शोएब चार अन्य लोगों के साथ केरल गया था। वहां फर्जी कंपनियों के नाम से करंट खाते खोले गए। इसके बाद सिद्धिकी महमदसिद्दिक मुफीदभाई, शेख रियाजुद्दीन इम्तियाज, हमजा हुमायू और कमालशाह कादरशाह को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया।

केरल से दो गिरफ्तार: पुलिस ने केरल से जमालुद्दीन फैसल और मुजामिल थैब को गिरफ्तार किया।

पंजाब से दो गिरफ्तार: सरबजीत सिंह और सोनिया शर्मा को पकड़ा गया। इन दोनों पर म्यूल बैंक खातों को संभालने का आरोप है।

फीस या मार्जिन के नाम पर ठगी

इस नेटवर्क के झांसे में फंसे लोग जब रकम निकालने की कोशिश करते थे, तो उनसे टैक्स, ब्रोकरेज, आईपीओ चार्ज, वेरिफिकेशन फीस या मार्जिन के नाम पर पैसे मांगे जाते थे।

भारत का अरुणाचल का मैप जारी करना गलत: चीन

कहा...इससे हमारा दावा नहीं बदलेगा; भारत का जवाब- यह हमारा अटूट हिस्सा

नई दिल्ली। चीन ने सोमवार को कहा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को अपने मैप पर दिखाना गलत है। चीन ने इसे 'अमान्य' करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन भारत की ओर से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश के मैप को मान्यता नहीं देता। चीन की आपत्ति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, अरुणाचल भारत का एक अटूट और अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा तथ्य है जो खुद-ब-खुद स्पष्ट है और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया था।

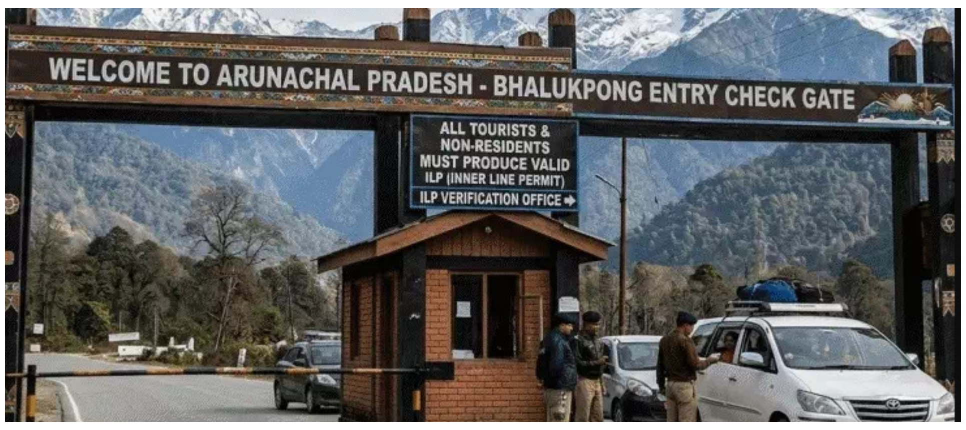

यह कदम चीन की ओर से राज्य की जगहों के नाम बदलने की कोशिशों के बीच उठाया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह काम अरुणाचल प्रदेश सरकार से सलाह लेकर किया गया है। इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान बताना और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

सरकार ने ऐसा क्यों किया

इन नामों को आधिकारिक मानचित्रों में शामिल करने का मकसद प्रशासन को बेहतर बनाना है। इससे सरकारी रिकॉर्ड में एकरूपता आएगी, अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल होगा और आपदा के समय मदद पहुंचाने में आसानी होगी। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इन नामों के आधार पर लोगों के पासपोर्ट या दूसरे निजी दस्तावेजों में कोई बदलाव किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों की आधिकारिक पहचान तय करना और भारत के प्रशासनिक रिकॉर्ड में उन्हें शामिल करना है।

चीन अरुणाचल की जगहों के नाम जारी करता रहा है

चीन ने कई बार अरुणाचल प्रदेश की जगहों के चीनी नामों की सूची जारी करता रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है। भारत ने चीन की इन कोशिशों को लगातार खारिज किया है। भारत का कहना है कि इनका भारत की राज्य पर संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता।

एअर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस जांच, दावा-पायलट ने गांजा पिया था

दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव; फुकेट-दिल्ली फ्लाइट झटके से 300 फीट नीचे आ गई थी

नई दिल्ली। एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट-इन-कमांड का कन्फर्मेटरी डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। टर्बुलेंस हादसे के बाद दिल्ली लैंडिंग पायलट का स्क्रीनिंग टेस्ट नॉन-नेगेटिव आया था। इसके बाद एक कन्फर्मेटरी टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पायलट के दूसरे ड्रग टेस्ट में बात सामने आई है कि उसने गांजा पिया था। यह घटना 4 अगस्त को एअर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट के साथ हुई थी। जिसमें 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन भुवनेश्वर से गुजरते समय अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था। जिससे यात्रियों और क्रू सदस्यों को चोटें आई थीं। इसके बाद दिल्ली में लैंडिंग हुई थी। जांच पूरी होने तक DGC ने फ्लाइट क्रू के दोनों सदस्यों को रोस्टर से हटा दिया है। एअर इंडिया ने सोमवार को कहा कि वह फुकेत-दिल्ली उड़ान की घटना से जुड़े जांच निष्कर्षों या टिप्पणियों पर बयान नहीं दे सकती। एयरलाइन ने कहा कि AAIB प्रावधानों के तहत जांच कर रहा है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, घटना की जांच जारी है, इसलिए एअर इंडिया जांच से जुड़े किसी पॉइंट पर बयान नहीं दे सकती। हम जरूरत के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग देते रहेंगे।

दो से अधिक बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत-निकाय चुनाव, राजस्थान सरकार ने बदला तीन दशक पुराना नियम

जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार ने चुनावी पात्रता से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान को समाप्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही तीन दशक से चली आ रही दो-संतान की अनिवार्यता अब स्थानीय चुनावों में उम्मीदवार बनने की राह में बाधा नहीं रहेगी। यह प्रावधान 1990 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत और नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवार नहीं बन सकते थे। अब सरकार का तर्क है कि बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में इस प्रावधान की प्रासंगिकता कम हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक-2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित संशोधनों के जरिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संबंधित पात्रता शर्त और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में मौजूद दो-संतान संबंधी प्रतिबंध को हटाने का रास्ता साफ किया गया। बाद में राजस्थान विधानसभा ने नगरपालिका कानून में संशोधन को मंजूरी भी दी। सरकार के फैसले से स्थानीय राजनीति में ऐसे अनेक संभावित उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल सकता है, जो अब तक केवल संतान संख्या के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसका असर विशेष रूप से ग्रामीण राजनीति में दिखाई देने की संभावना है, जहां पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा

लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया; ममेरे भाई को पिंजरे में कोर्ट लाया गया

दमिश्क। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद और उनके छोटे भाई माहेर अल-असद को फांसी की सजा सुनाई। दोनों को गृहयुद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामलों में दोषी ठहराया गया। इसी मामले में बशर अल-असद के मामा के बेटे अतीफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई गई। बशर और माहेर दिसंबर 2024 में सरकार गिरने के बाद रूस भाग गए थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण दी हुई है। दोनों की गैरमौजूदगी में सजा सुनाई गई। अतीफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को कैदी की वर्दी पहनाकर पिंजरे में कोर्ट लाया गया। अतीफ नजीब सीरियाई सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। 2011 में वे दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख थे। वह असद सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक हैं, जिन पर अदालत में मुकदमा चला।

भाजपा के झारखंड बंद का मिलाजुला असर: स्कूल-दफ्तर खुले, कई जगह बाजार बंद

विधानसभा घेराव के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं-पुलिस में झड़प हुई थी

रांची। झारखंड के रांची में सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद बुलाया। रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कें जाम कीं। कुछ जिलों में कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराते भी नजर आए। कई शहरों में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि, कई प्राइवेट स्कूल खुले हुए थे। इधर, झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, जबकि कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए। पुलिस लगातार उन्हें हटाने की कोशिश करती रही, इसी दौरान धक्का-मुक्की और झड़प हुई। वहीं, मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, विपक्ष हल्ला करता रहेगा, हम अपना काम करते जाएंगे। सरकार छात्रों के हित में फैसले ले रही है। सीएम सोरेन ने कहा- परजीवी भाजपा

ने कल भी युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। छात्रों की बात...छात्रों के साथ होगी और झारखंड के मेरे युवा साथियों को न्याय मिलकर रहेगा।

लाठीचार्ज में 100 से अधिक छात्र घायल

छात्रों ने सोमवार को झारखंड में छ्क्रस्ट-छ्रस्स्ट भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विधानसभा घेराव के दौरान 100 से अधिक छात्र घायल हुए। कई छात्रों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है। वहीं, रांची पुलिस के करीब 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सरकार और छात्रों के बीच अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। हालांकि सरकार ने छात्रों की 9 में से 6 मांगें मान ली हैं। छात्रों का कहना है कि अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही बातचीत करेंगे। वहीं, भाजपा का आरोप है कि झारखंड सरकार छात्रों की मांगों पर बातचीत करने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की।

देवेंद्र नाथ महतो से अस्पताल से जारी किया खुला पत्र

वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से अस्पताल से खुला पत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, विधानसभा घेराव कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने वाले सभी सहयोगियों को धन्यवाद। शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सम्पूर्ण न्याय तक संघर्ष जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो का अस्पताल में भी 10वें दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है।

सीएम सोरेन बोले- परजीवी की तरह जीवित है विपक्ष

विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, पिछले दो-चार दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, उसे देखकर हमें लगता है कि अब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन कभी-कभी वे अलग-अलग तरीकों की आड़ में छिपकर बैठे रहते हैं और अलग-अलग स्रोतों के सहारे खुद को जीवित रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई परजीवी जीवित रहता है।

कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ चोर-चोर के नारे लगे

3 दिन में दूसरी घटना; कार पर पत्थर और कीचड़ फेंका गया था

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में मंगलवार को कुछ लोगों ने चोर, चोर के नारे लगाए। यह ममता के साथ 3 दिन में दूसरी घटना है। रविवार को हलीसहर में भी ममता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। TMC ने कोलकाता में यह कार्यक्रम बीजेपी सांसद नागेंद्र रॉय की नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में रखा था। नारे लगने से कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुक गया था।

नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं ममता

ममता नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग पर पहुंची थीं। उनके हाथ में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की फोटो थी। जब कार्यक्रम चल रहा था, तभी कुछ लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने ममता 'चोर-चोर' के नारे लगाना शुरू कर दिए। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थित लोगों ने जानबूझकर प्रदर्शन करवाया। पार्टी के मुताबिक, इसका मकसद कार्यक्रम को रोकना और ममता बनर्जी का अपमान करना था।

बीजेपी सांसद ने नेताजी को वॉर क्रिमिनल कहा था

नागेंद्र रॉय ने नेताजी को वॉर क्रिमिनल बताया था। उन्होंने नेताजी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज की भूमिका पर भी संदेह जताया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं ने इन बयानों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने साफ किया कि रॉय की टिप्पणी पूरी तरह निजी थी। पार्टी न तो इसका समर्थन करती है, न ही इसे मानती है। टीएमसी ने इन टिप्पणियों को बंगाल की राष्ट्रवादी विरासत और नेताजी की राजनीतिक पहचान पर हमला बताया।

हलीसपुर में ममता की कार को लोगों ने घेर लिया था

9 अगस्त को भी ममता ने खुद पर हमले का दावा किया था। ममता नॉर्थ 24 परगना जिले के हलीसहर में टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गई थीं। आरोप है कि इस कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जब ममता, कार्यकर्ता के घर पहुंचीं तो लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था। चोर-चोर के नारे लगाए। ममता का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर कीचड़ और चप्पलें भी फेंकी गई थीं। भीड़ बढ़ने पर पुलिसकर्मियों ने ममता की गाड़ी के चारों ओर घेरा बनाया था। हालांकि बीजेपी ने हलीसहर की घटना में शामिल होने से इनकार किया है। उसके नेताओं ने प्रदर्शन को ममता के खिलाफ जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति बताया।

8 जुलाई: ममता ने घर के बाहर 3 लोगों को थप्पड़ मारा

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 8 जुलाई को टीएमसी की रैली में हंगामा हो गया था। इस दौरान ममता बनर्जी नाराज हो गई। वे अपनी ही पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारते नजर आईं थीं। दरअसल, रैली बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप-मर्डर के विरोध में निकाली जा रही थी। इस दौरान चोर-चोर के नारे लगने लगे और कुछ लोगों ने रैली में शामिल लोगों पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। टीएमसी ने आरोप लगाया कि हंगामा भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान मारपीट भी की। ममता ने कहा कि बंगाल में अराजकता फैल गई है। पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है।

सांसद सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे मोदी-शाह

सोनिया-राहुल और प्रियंका भी मौजूद रहे; पीएम कुछ घंटे पहले NCP सांसदों से भी मिले थे

नई दिल्ली। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता सोमवार को एनएसपी (शरद गुट) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे। इस दौरान शाह और मोदी एनएसपी(शरद गुट) प्रमुख शरद पवार के साथ बैठे दिखे। कार्यक्रम में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इससे कुछ घंटे पहले ही शरद पवार की पार्टी के 8 सांसदों के साथ मुलाकात भी की। मोदी और पवार की साथ बैठे फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले, 22 जुलाई को शरद पवार और सुप्रिया सुले ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन पर एनसीपी के संभावित रुख को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों के बीच हुई। पहले सूत्रों ने संकेत दिया था कि पवार की पार्टी कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है। ऐसा होने पर पार्टी इंडिया ब्लॉक के कुछ दलों से अलग रुख अपना सकती है। हालांकि, सुप्रिया सुले ने कहा है कि अंतिम कानून देखने के बाद ही पार्टी अपना रुख तय करेगी। जून में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एनडीए में शामिल होने या कांग्रेस में विलय की अटकलें सामने आई थीं। हालांकि, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने इन सभी चर्चाओं को अफवाह बताया है।

जयपुर के कोचिंग सेंटरों पर नजर, 'संस्थागत उपयोग' और व्यावसायिक क्षेत्र का विवाद गहराया

नई दिल्ली/जयपुर। जयपुर के व्यावसायिक क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों और संस्थागत गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाते हुए JDA से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत के समक्ष यह मामला रखा गया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संस्थागत गतिविधियों के कारण आसपास रहने वाले लोगों को असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में कोचिंग संस्थानों के संचालन का मुद्दा भी अदालत के सामने आया। मामले को और गंभीर बनाने वाला तथ्य यह है कि अदालत को बताया गया कि कोचिंग जैसे संस्थागत उपयोग के लिए बहुमंजिला भवन पहले से उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन उन्हें कोचिंग संस्थानों को स्थानांतरित करने के बजाय कथित तौर पर अन्य संस्थानों को आवंटित किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने JDA से पूछा है कि इस स्थिति में सुधार के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं।

व्यावसायिक क्षेत्र में संस्थागत गतिविधि क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया मुद्दा केवल कोचिंग सेंटरों के अस्तित्व का नहीं, बल्कि भूमि उपयोग और शहरी नियोजन के अनुपालन का है। व्यावसायिक क्षेत्र में जब बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करने वाली कोचिंग गतिविधियां संचालित होती हैं तो उसके साथ यातायात, पार्किंग, सड़क पर भीड़, पैदल आवाजाही और स्थानीय निवासियों की सुविधा जैसे सवाल भी जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि किसी क्षेत्र का भू-उपयोग तय करते समय गतिविधियों के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। अदालत के समक्ष अब सवाल यह है कि यदि ऐसी संस्थागत गतिविधियों के लिए अलग व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी तो फिर व्यावसायिक क्षेत्रों में उनका संचालन जारी क्यों रहा?

कोचिंग के लिए भवन बने तो दूसरे संस्थानों को आवंटन क्यों?

मामले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उन बहुमंजिला भवनों से जुड़ा है जिन्हें कथित तौर पर कोचिंग संस्थानों जैसे संस्थागत उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था। अदालत को बताया गया कि कोचिंग संस्थानों को इन भवनों में स्थानांतरित किया जाना था। इसके बावजूद इन भवनों को दूसरे संस्थानों को आवंटित किए जाने की स्थिति सामने आई। क्या भवन का मूल उद्देश्य बदला गया? यदि बदला गया तो किस आधार पर? कोचिंग संस्थानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? और क्या दूसरे संस्थानों को किया गया आवंटन मूल नियोजन के अनुरूप है? इन सवालों का जवाब **JDA** को सुप्रीम कोर्ट के सामने देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने **JDA** के अधिवक्ता को पूर्ण निर्देश प्राप्त करने और तीन सप्ताह के भीतर उठाए गए विशिष्ट उपचारात्मक एवं सुधारात्मक कदमों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह महज स्थिति रिपोर्ट मांगने जैसा सामान्य निर्देश नहीं है। अदालत ने विशेष रूप से यह जानना चाहा है कि समस्या के समाधान के लिए वास्तविक स्तर पर क्या कदम उठाए गए।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रदीप कुमार सोलंकी द्वारा महानगर मल्टीमीडिया प्रा. लि. जी-848, फेज 3, रीको सीतापुरा, जयपुर (राज.) से मुद्रित एवं 227-हीरालाल की गली, झालाना, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित।
सम्पादकः प्रदीप कुमार सोलंकी, मो. 93510-01100, Email: atulyasansar@gmail.com संपादकीय कार्यालयः जगतपुरा फ्लाईओवर के पास, जगतपुरा जयपुर।